ECONOMICS (1)

B.A. Part Two
Paper IIIrd

by :-
Dr. Shailesh Kumar
dept. of economics
Raja Singh College Siwan.

16.5.20

भारत में खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य स्वावलंबन :-
(Food Security & food Self-Sufficiency in India)

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में योजनाकरण का प्रारंभ से ही एक प्रधान उद्देश्य खाद्य का स्वावलंबन एवं खाद्य की सुरक्षा रहा है। विश्व के खाद्य आपूर्ति करने वाले विकसित राष्ट्र खाद्यान्नों की आपूर्ति कुछ शर्तों के साथ ही देते हैं। भारत को 1965-तथा 66 के दो भयानक सूखे की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करना पड़ा। इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में पहल किया। परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा। खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथा उनके आयात की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई। नौवीं योजना ने खाद्य सुरक्षा पर जोर देते हुए यह विचार किया कि "One of the first effort of the country were to build up a food Security System to ensure that the three of famine no longer mars the country". देश को पिछले प्रायः चार दशकों में अकाल की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है यह सरकार के इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा सबूत है।

(i) 1950-51 से 1999-2000 के बीच खाद्यान्न का उत्पादन 508 लाख टन से बढ़कर 2090 लाख टन यानी चार गुना से भी अधिक हो गया।

(ii) 1950-51 में खाद्यान्न पदार्थों के कुल उत्पादन में खाद्यान्न का प्रतिशत 84 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2001 में 99 प्रतिशत हो गया जबकि दालों का उत्पादन 16.5 प्रतिशत से घटकर 7.4 प्रतिशत हो गया।

(iii) खाद्यान्नों में भी चावल एवं गेहूँ का उत्पाद अनुपात 1950-51-

P.T.O.

Scanned by CamScanner

के प्रतिशत से (63 प्रतिशत से) बढ़कर 1999-2000 में 77 प्रतिशत हो गया तथा मोटे अनाजों का प्रतिशत 30 से घटकर 11 प्रतिशत हो गया।

इस प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि देश में दालों का अभाव एक महान समस्या है। अतः खाद्य नीति का उद्देश्य दालों की आपूर्ति बढ़ाना तथा इन्हें अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

योजना आयोग के अनुसार "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि जो मुख्यतः उपभोग के लिए खाद्य के घरेलू उत्पादन पर विश्वास रखती है, और साथ ही बफर स्टॉक कायम करना चाहती है। आत्मनिर्भरता की रणनीति कही गयी है।" यह रणनीति भारतीय आयोजन के आरंभिक चरण में अपनायी गई थी। इसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मुख्य उद्देश्य था। और 1960-70 के दशक में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी अपनाई गई जिसे हरित क्रांति भी कहा गया। इस निरंतर प्रयास से हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

यद्यपि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकि है, परन्तु अभी भी जनसंख्या संतुलित भोजन का अभाव महसूस करती है यह चिंता का विषय है कि चाहे अनाज का उत्पादन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ बढ़ता गया है और अनाज के औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग में गिरावट आयी है।

परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धि से है जो कि परिमाण गुणवत्ता और सामर्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त हो। अतः इस संदर्भ में खाद्य पदार्थों की कीमतों और जनसंख्या के पास उपलब्ध क्रयशक्ति का प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। गरीब वर्गों की सहायता के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दोहरी कीमत प्रक्रिया अपनाया है। सार्वजनिक वितरण के केन्द्रों पर खाद्य पदार्थों की जारी कीमत को बाजार कीमत से कम रखा गया है ताकि गरीब तबके के लोग खाद्य पदार्थ आसानी से खरीद सके। परन्तु राजनीतिक दबावों के कारण सरकार ने सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनायी न कि एक लक्षित प्रणाली जिसका केन्द्र गरीब हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे सरकार की खाद्य सुरक्षा में एक केन्द्रीय उपकरण समझा गया, ऐच्छिक परिणाम नहीं दे सका। इसका विवरण नौवीं योजना में इस प्रकार किया गया।

Scanned by CamScanner

" बढ़ते हुए खाद्य सहायताओं (Food Subsidies) के बावजूद, मूल्यांकन संबंधी उपलब्ध अध्ययनों खाद्य, ये संकेत मिलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपलब्ध कराए गए खाद्य, परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा में सुधार नहीं ला सके। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की उचित किमतों पर उपलब्धि, गरीबों के लिए परिवार स्तर पर, खाद्य सुरक्षा का रूप धारण न कर सकी।

अतः भारत में परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्न दिशाओं में भी प्रयास करना होगा

(1) ऐसी विकास रणनीतियाँ और समर्पित आर्थिक नीतियाँ अपनानी होगी जो समता के साथ-साथ विकास की परिस्थितियाँ कायम करें।

(2) खाद्य एवं अन्य कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर त्वरित करनी होगी जिससे लिये खाद्य खरीदने की शक्ति प्राप्त हो सके।

(3) ऐसे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना होगा जिसका केन्द्र बिंदु गरीब वर्ग हो।

(4) गरीब वर्गों के लिए सस्ते ऋण उपलब्ध कराना।

(5) रोजगार अवसरों को बढ़ाना।

(6) आय हस्तांतरण योजना चलाना जिसमें सस्ती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना भी शामिल है।

(7) खाद्य के संवरण और किमतों को स्थिर करना।

(8) आपात काल में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए, विशेषकर प्राकृतिक विपदाएं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि। के लिए देश को तैयार रखना।

खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अंग :—

(a) देशीय उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग पूरी की जा सके। तथा अल्पपोषण को कम किया जा सके।

(b) खाद्य पदार्थों की वसूली (Procurement) और संग्रहण के लिए न्यूनतम समर्थन किमतें उपलब्ध कराना।

(c) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाना। और

(d) बफर स्टॉक कायम करना ताकि प्राकृतिक विपत्तियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अस्थायी दुर्लभता का मुकाबला करना और व्यापारियों की ऐसी क्रियाओं जिनके द्वारा वे विशेषकर दुर्लभता के काल में खाद्य की कीमतों को ऊपर धकेलने के प्रयास करने वालों के विरुद्ध प्रतिरोध का कार्य करना।

निष्कर्ष

गत वर्ष 50 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन जो 1950-51 में ऊपर में आँकड़े दिए गये हैं तुलनात्मक रूप से अनाज के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या के वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक तेज थी। परन्तु दालों के संदर्भ में यह वृद्धि दर जनसंख्या के वृद्धि दर से भी पीछे रह गयी। इस प्रकार और अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 116 ग्राम से घटकर 90 ग्राम प्रतिदिन हो गयी।

चिन्ता का एक और क्षेत्र उद्यान कृषि पर पर्याप्त जोर न देना इस प्रकार देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पाई है। तथा इस संबंध में और अधिक व्यापक प्रयासों की अनिवार्यता है जिसके परिणामस्वरूप सब्जियाँ विशेषकर हरी-पत्तेदार, पीली/लाल सब्जियाँ ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों में पूरे वर्ष के दौरान सहनीय कीमत पर उपलब्ध कराने की योजना एक सपना ही रह गया।

आय स्तर का दालों, दूध फलों, मांस, तेल और चीनी के उपभोग से सकारात्मक संबंध है। चूंकि दालों के उपभोग के लिए 40 ग्राम प्रतिदिन की सिफारिश की गई है 1996 में इसका राष्ट्रीय औसत उपभोग 34 ग्राम ही होने से यह साफ पता चलता है कि गरीबों की हालत दाल के उपभोग के संबंध में और भी खराब है। क्षेत्रीय आधार पर केवल कर्नाटक मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश औसत उपभोग से ऊँचा है। जब तक दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं की जाती है तब तक पोषण स्तर और अधिक गिरने की संभावना प्रबल दिखती है।